भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4292
उत्तर देने की तारीख 18 मार्च, 2026

मोबिलिटी और फाइबर-टू-द-होम में बीएसएनएल के राजस्व संबंधी प्रदर्शन

4292. श्री बी. वाई. राघवेन्द्रः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मोबिलिटी और फाइबर-टू-द-होम में बीएसएनएल के राजस्व संबंधी प्रदर्शन का सेवा-खंड-वार और क्षेत्र-वार आकलन किया है और यदि हाँ, तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों में राजस्व में हुई वृद्धि और उपभोक्ता प्रवृत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बीएसएनएल की 4जी सेवाओं की शुरुआत की वर्तमान स्थिति क्या है और शुरू किए गए स्थलों की संख्या, प्राप्त कवरेज, पूरे देश में विस्तार की समय-सीमा और 5 जी सेवाओं की शुरुआत के लिए रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पहाड़ी, वनाच्छादित और भौगोलिक रूप से उन चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कोई विशिष्ठ रणनीति तैयार की है, जहाँ नेटवर्क विस्तार को भौगोलिक बाधाओं और व्यावसायिक व्यवहार्यता की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और यदि हाँ, तो सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) या अन्य नीति संबंधी तंत्रों के माध्यम से सहयोग सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ग्रामीण और कठिन क्षेत्रों में विश्वसनीय मोबाइल और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए कोई सेवा-गुणवत्ता मानक, कवरेज संबंधी दायित्व निर्धारित किए गए हैं और इन क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की संतुष्टि बढ़ाने तथा ग्राहकों के कंपनी छोड़ने की दर कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बीएसएनएल के एफटीटीएच और गतिशीलता राजस्व प्रदर्शन का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	एफटीटीएच राजस्व (करोड में)	मोबिलिटी राजस्व (करोड में)
1	2022-23	2,071	5,638
2	2023-24	2,652	5,319
3	2024-25	2,923	5,503

(ख) आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप, बीएसएनएल अखिल भारतीय तैनाती के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एक लाख 4जी साइटों को शुरू कर रहा है। 28.02.2026 तक, कुल 97,906 4जी साइटें संस्थापित की गई हैं और 96,103 4जी साइटें चालू हैं। यह उपकरण प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य से 5जी में उन्नत करने योग्य हैं।

(ग) और (घ) पहाड़ी, वन और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों सहित देश में दूरसंचार अवसंरचना को मजबूत करने के लिए, सरकार विभिन्न योजनाओं जैसे 4जी संतृप्ति स्कीम, बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) / बॉर्डर इंटेलीजेंस पोस्ट(बीआईपी) आदि को लागू कर रही है। इन योजनाओं का विवरण **https://usof.gov.in** पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, मांग के आधार पर सभी ग्राम पंचायतों और गांवों तक फाइबर का विस्तार करने के लिए 04.08.2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1.39 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 करोड़ हाई स्पीड एफटीटीएच ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रावधान करना भी शामिल है। बीएसएनएल इस योजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) नियमित आधार पर सेवा प्रदाताओं से लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) वार प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) एकत्र करके विभिन्न सेवा गुणवत्ता मानकों के बेंचमार्क के अनुसार सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन की निगरानी करता है, जैसा कि क्यूओएस विनियमों अर्थात् "एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक विनियम, 2024 (2024 का 06) दिनांक 2 अगस्त 2024' में निर्धारित किया गया है। प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) ट्राई की वेबसाइट (**https://trai.gov.in/release-publication/qos-reports/pmr-reports)** पर प्रकाशित की जाती है। जहां भी सेवा गुणवत्ता बेंचमार्क पूरा नहीं किया जाता है, वहां संबंधित सेवा प्रदाता से स्पष्टीकरण मांगा जाता है और सेवा प्रदाता की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद अननुपालन वाले क्यूओएस मानकों के लिए सेवा प्रदाता पर वित्तीय निरूत्साहन शुल्क लगाया जाता है।

*****